एफडीआई :19 कंपनियां करेंगी 25 हजार करोड़ का निवेश

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बनाई गई नीतियों में दो ने निवेशकों को काफी आकर्षित किया है। औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत 121 कंपनियां आई हैं। इनमें 44 कंपनियों को 36 हजार करोड़ रुपये के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किया गया है।

रोजगार प्रोत्साहन नीति को निवेशकों ने लिया हाथों हाथ

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के तहत 19 कंपनियां प्रदेश में 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। प्रदेश सरकार ने देश-दुनिया की बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने को 25 से ज्यादा सेक्टोरल पॉलिसी बनाई हैं। इन नीतियों के तहत निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी, भूमि सब्सिडी, मशीन सब्सिडी, बिजली शुल्क, स्टांप शुल्क और जीएसटी में छूट सहित ढेरों सौगातों का प्रावधान है।

प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत मिलने वाली रियायतों ने कॉरपोरेट घरानों का ध्यान खींचा है। मार्च 2025 तक 121 कंपनियां आवेदन कर चुकी हैं, जो करीब 2.28 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। प्रस्तावों की स्क्रूटनी के बाद 44 कंपनियों को सरकार ने लेटर आफ कंफर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो

छह प्रस्तावों को मंजूरी का इंतजार

करीब 2682 करोड़ के छह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। हाई लेवल इम्पावर्ड कमेटी के पास चार प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं। इनके जरिये 9900 करोड़ रुपये का निवेश होना है। इम्पावर्ड कमेटी के पास 381 करोड़ रुपये के लिए तीन प्रस्ताव लंबित हैं। विभिन्न सेक्टर के सात प्रस्ताव स्थगित हो गए हैं। इनसे करीब 46 हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित था। वहीं, 34 प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं।

9200 करोड़ के प्रस्ताव अंतिम चरण में

एफडीआई पालिसी के तहत 11 वैश्विक कंपनियों को लेटर ऑफ क्रेडिट और इनकंब्रेंस सर्टिफिकेट (ईसी) जारी हो चुका है। इनमें चार प्रस्ताव भूमि सब्सिडी समेत अन्य रियायतों की मंजूरी के इंतजार में हैं। करीब 9200 करोड़ के तीन प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं। तीन स्थगित हो गए हैं। 1785 करोड़ के एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का प्रस्ताव भी आया है।